

भाग-I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2025

संख्या लैज. 17/2025.— दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असेम्बली (फैसिलिटिज टू मैम्बर्स) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 20 मई, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16**हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2025****हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) अधिनियम, 1979****को आगे संशोधित करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) अधिनियम, 1979 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“3.सुविधाएं.— (1) ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं के अध्यक्षीन, जो विहित की जाएं, प्रत्येक सदस्य को,—

 - (i) निर्मित गृह या फ्लैट खरीदने के लिए या गृह निर्माण के लिए या सहकारी ग्रुप आवासीय सोसाइटी, जिसका वह सदस्य है, द्वारा निर्मित किए जाने वाले फ्लैट के लिए गृह निर्माण अग्रिम के रूप में; या
 - (ii) मोटर कार खरीदने या उसकी पूर्वानुमानित कीमत हेतु; या
 - (iii) खण्ड (i) और (ii) दोनों के लिए,

प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में एक करोड़ रुपए से अनधिक राशि का भुगतान किया जा सकता है:

परन्तु साठ वर्ष की आयु से कम का ऐसा सदस्य, जिसने प्रथम बार खण्ड (i), (ii) या (iii) के अधीन प्रतिसंदेय अग्रिम लिया था, पूर्व अग्रिम के मूलधन और उस पर ब्याज, जैसी भी स्थिति हो, की सम्पूर्ण वसूली होने के तुरन्त बाद दूसरी बार प्रतिसंदेय अग्रिम लेने का हकदार हो सकता है:

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती गृह निर्माण अग्रिम और उस पर ब्याज के प्रतिदाय पर, साठ वर्ष की आयु से कम का ऐसा सदस्य, समरूप निबन्धनों तथा शर्तों पर प्रथम बार के लिए उस द्वारा पहले से लिए गए गृह निर्माण अग्रिम के मूलधन के पचास प्रतिशत के बराबर तीसरी बार प्रतिसंदेय गृह निर्माण अग्रिम लेने का हकदार हो सकता है।

(2) कोई सदस्य अपने गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करवाने के लिए अधिकतम दस लाख रुपए तक लेने का भी हकदार होगा:

परन्तु यदि कोई सदस्य गृह निर्माण अग्रिम ले चुका है, तो वह दस लाख रुपए की उक्त राशि लेने का भी हकदार होगा, यदि गृह निर्माण अग्रिम के बकाया मूलधन के सापेक्ष दस लाख रुपए के बराबर की राशि का प्रतिसंदाय पहले से ही किया जा चुका हो।”।

1979 के
हरियाणा
अधिनियम 9 की
धारा 5 का
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, “के खण्ड (क)” शब्दों तथा चिह्नों का लोप कर दिया जाएगा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।